



रोज़गार बाज़ार में बढ़ता कौशल अंतराल

प्रलिम्स:

[सकल घरेलू उत्पाद \(GDP\)](#), [आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24](#), [वैश्विक नवाचार सूचकांक \(GII\)](#), वनिरिमाण क्षेत्र से संबंधित पहल

मेन्स:

भारत में वनिरिमाण क्षेत्र के विकास चालक, भारत के वनिरिमाण क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत के रोज़गार बाज़ार में अर्द्ध-कुशल और उच्च-कुशल रोज़गार के बीच वभिजन बढ़ रहा है। वगित दो दशकों में [सेवा क्षेत्र](#) (वशिष रूप से आईटी, बैंकिंग और वतित) आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक रहा है। इसके वपिरीत, परधिन और फुटवयिर जैसे [पारंपरिक उद्योग](#) (जो अर्द्ध-कुशल रोज़गार प्रदान करते हैं) स्थरि हो रहे हैं।

भारत के वनिरिमाण एवं सेवा क्षेत्र के वर्तमान रुझान क्या हैं?

■ सेवा क्षेत्र:

- [सकल घरेलू उत्पाद और रोज़गार में योगदान](#): भारत के सेवा क्षेत्र का [सकल घरेलू उत्पाद \(GDP\)](#) में 50% से अधिक का योगदान है तथा इससे लगभग 30.7% आबादी को रोज़गार मलिता है एवं यह सॉफ्टवेयर सेवाओं हेतु वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- [रकिवरी और संवृद्धि](#): सेवा क्षेत्र में वतित वर्ष 2022-23 में उल्लेखनीय सुधार हुआ और वर्ष-दर-वर्ष (YoY) 8.4% की वृद्धि दर दर्ज की।
 - भारतीय आईटी आउटसोर्सिंग बाज़ार वर्ष 2021 और 2024 के बीच 6-8 % तक बढ़ने का अनुमान है।
- [GII रैंकिंग](#): सतिंबर 2023 में भारत ने तकनीकी रूप से गतशील, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार योग्य सेवाओं की प्रगति से प्रेरित होकर [वैश्विक नवाचार सूचकांक \(GII\)](#) में अपना 40वाँ स्थान बनाए रखा।
- [FDI](#): सेवा क्षेत्र में [सर्वाधिक प्रत्यक्ष वदिशी निवेश \(FDI\)](#) आकर्षित हुआ, जो अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक 109.5 बलियिन अमेरिकी डॉलर रहा।

■ वनिरिमाण क्षेत्र:

- [वनिरिमाण क्षेत्र में स्थरिता](#): वनिरिमाण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% (जो लक्षित 25% से कम है) बना हुआ है, जिससे उच्च-कुशल और अर्द्ध-रोज़गार के बीच का अंतराल बढ़ रहा है।
- [वनिरिमाण की कमज़ोर स्थिति](#): भारत का वनिरिमाण क्षेत्र बांग्लादेश, थाईलैंड और वयितनाम जैसे प्रतस्पर्द्धियों से पीछे है, जिससे अर्द्ध-कुशल रोज़गार सृजन प्रभावित हो रहा है।
 - अर्थशास्त्री इस बात पर ज़ोर देते हैं कि भारत अपनी 1.4 अरब वशिल जनसंख्या के कारणकेवल सेवा क्षेत्र पर निर्भर नहीं रह सकता है।
- [रोज़गार सृजन की आवश्यकता](#): [आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24](#) के अनुमान के अनुसार प्रतविर्ष 7.85 मलियन गैर-कृषि रोज़गारों की आवश्यकता होगी, जो बढ़ते कार्यबल को समायोजित करने के लयि वभिन्न क्षेत्रों में रोज़गारों के सृजन की व्यापक आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
 - [सेंटर फॉर मॉनटरिंग इंडियन इकोनॉमी \(CMIE\)](#) के अनुसार, जून 2024 में राष्ट्रीय बेरोज़गारी दर 7% से बढ़कर 9% हो जाएगी।

वनिरिमाण क्षेत्र में रोज़गार में गरिवट के लयि कौन-से कारक ज़मिमेदार हैं?

- [वनिरिमाण क्षेत्र में स्थरिता](#): वनिरिमाण क्षेत्र में स्थरिता (GDP में मात्र 14% का योगदान) से शर्म-प्रधान क्षेत्रों में रोज़गार सृजन में बाधा

उत्पन्न हुई है।

- भारत का सेवा नरियात वैश्विक वाणज्यिक सेवा नरियात का 4.3% है, जबकि इसका वस्तु नरियात वैश्विक वस्तु बाज़ार का केवल 1.8% है। इस असंतुलन के कारण भारत के वनिरिमाण क्षेत्र में सीमति रोज़गार सृजति होते हैं।
- उच्च-कौशल वाले उद्योगों की ओर बदलाव: वनिरिमाण क्षेत्र को नज़रअंदाज़ करते हुए वैश्विक कषमता केंद्रों (GCC) के उदय से उच्च-कौशल वाले आईटी पेशवरों के लिये रोज़गार के अवसरों में वृद्धि हुई है लेकिन यह बदलाव पर्याप्त अर्द्ध-कौशल वाले रोज़गार सृजन में परणित नहीं हुआ है।
 - भारत में GCC की संख्या में वृद्धि हुई है, जनिमें से लगभग 1,600 बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापति किये गए हैं, जो डेटा एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर वकिसास पर केंद्रित हैं।
- नरियात-संबंधी रोज़गार में गरिावट: वशि्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नरियात-संबंधी रोज़गार वर्ष 2012 के कुल घरेलू रोज़गार के 9.5% से घटकर वर्ष 2020 में 6.5% हो गए हैं।
 - इस गरिावट का कारण भारत के सेवा क्षेत्र और उच्च कौशल वनिरिमाण का नरियात क्षेत्र में प्रभुत्व होना है, जो व्यापक कार्यबल हेतु रोज़गार सृजन में कम प्रभावी है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार से संबंधित रोज़गार सृजन में कमी आई है।
- वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVC) में सीमति भागीदारी: GVC में भारत की घटती भागीदारी के कारण रोज़गार सृजन सीमति हो गया है जबकि GVC की वैश्विक व्यापार में 70% भागीदारी है।
 - वशि्व बैंक के अनुसार, कचचे माल की कमी और उच्च परिवहन लागत जैसी चुनौतियों ने भारत की व्यापार भागीदारी को कम कर दिया है।
- उच्च टैरफि: मध्यवर्ती वस्तुओं पर उच्च टैरफि ने भारतीय नरिमाताओं के लिये उत्पादन लागत बढ़ा दी है, जिससे उनकी वैश्विक प्रतस्पर्द्धात्मकता कम हो गई है।
 - भारत का औसत टैरफि वर्ष 2014 के 13% से बढ़कर संभावित रूप से वर्ष 2022 में 18.1% हो गया, जिससे वयितनाम और थर्डलैंड जैसे देशों के साथ प्रतस्पर्द्धा करना कठिन होने के साथ अर्द्ध-कुशल रोज़गार के अवसरों में कमी आई है।
- अर्द्ध-कौशल संबंधी वनिरिमाण में भारत द्वारा अवसर का लाभ न उठा पाना: भारत को वर्ष 2015 से 2022 के बीच अर्द्ध-कौशल वनिरिमाण से चीन के बाहर हो जाने से उत्पन्न अवसर का लाभ उठाने में संघर्ष का सामना करना पड़ा।
 - परिधान, चमड़ा, वस्त्र और फुटवियर जैसे उद्योगों में चीन की कम होती उपस्थिति से बांग्लादेश, वयितनाम जैसे देशों तथा यहाँ तक कि जर्मनी एवं नीदरलैंड जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को भी लाभ हुआ है।
- कौशल वकिसास का अभाव: भारत के केवल 16% श्रम बल को कौशल प्रशक्तिषण प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त व्यावसायिक कौशल और शक्तिषा के कारण रोज़गार की संभावना में कमी बनी हुई है। इंडिया स्किलस रिपोर्ट के अनुसार केवल 45% स्नातक ही रोज़गार योग्य हैं।

भारत में वनिरिमाण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये क्या पहल की गई हैं?

- PM मतिर पार्क: सरकार ने वर्ष 2023 में परिधान क्षेत्र में वशि्व स्तरीय बुनयिादी ढाँचे को वकिसति करने के लिये 4,445 करोड़ रुपए के निविश के साथ 7 पीएम मेगा इटीग्रेटेड टेकसटाइल रीजन एंड अपैरल (PM-MITRA) पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी।
- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा वकिसास कार्यक्रम: आर्थिक मामलों की मंत्रमिंडलीय समिति ने 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निविश के साथ 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य वनिरिमाण कषमताओं को बढ़ावा देना है।
- टैरफि में कटौती: केंद्रीय बजट 2024-25 में चकितिसा उपकरण और वस्त्र सहित विभिन्न वस्तुओं पर टैरफि में कटौती की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य उत्पादन लागत को कम करना तथा प्रतस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना है।
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): यह योजना गैर-कृषि इकाइयाँ स्थापति करने में उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों तथा बेरोज़गार युवाओं के लिये रोज़गार सृजति करना है।
 - वर्ष 2018-19 से 30 जनवरी, 2024 तक इस कार्यक्रम के तहत अनुमानित 37.46 लाख रोज़गार सृजति होना संभावित है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): इस योजना के तहत स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिये व्यक्तियों और सूक्ष्म/लघु व्यवसायों को 10 लाख रुपए तक का जमानत-मुक्त ऋण प्रदान करना शामिल है।
 - 29 मार्च, 2024 तक इस योजना के तहत लगभग 47.7 करोड़ ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं।

आगे की राह

- कौशल पहचान के लिये वकिेंद्रीकृत सामुदायिक कार्रवाई: यह दृष्टिकोण संभावित श्रमिकों की पहचान करने और उन्हें वशिषिट कौशल की आवश्यकता वाले उद्योगों के साथ जोड़ने में मदद कर, वनिरिमाण क्षेत्र को लक्षित कार्यबल प्रदान करता है।
- एकीकृत मानव वकिसास: स्थानीय स्तर पर शक्तिषा, स्वास्थ, कौशल और रोज़गार को एकीकृत करके तथा महिला समूहों का सहयोग प्राप्त कर अधिक स्वस्थ, अधिक कुशल कार्यबल का नरिमाण कया जा सकता है, जो वनिरिमाण क्षेत्र की उत्पादकता एवं समावेशिता दोनों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- वैश्विक मूल्य शृंखला (GVC) भागीदारी को बढ़ावा देना: कम टैरफि और सरलीकृत व्यापार के माध्यम से GVC में एकीकरण में सुधार करके, भारतीय नरिमाता बड़े बाज़ारों, आधुनिक प्रौद्योगिकियों तथा वैश्विक नेटवर्क तक पहुँच सकते हैं, जिससे वनिरिमाण क्षेत्र में प्रतस्पर्द्धा में वृद्धि होगी।
 - केंद्रीय बजट 2024-25 में कई प्रमुख वस्तुओं पर टैरफि में कटौती की घोषणा की गई है, लेकिन वशि्व बैंक का सुझाव है कि लागत असमानताओं को खत्म करने और प्रतस्पर्द्धात्मकता में सुधार करने के लिये तथा अधिक कटौती आवश्यक है।
- कौशल वकिसास में निविश: आधुनिक वनिरिमाण की उभरती मांगों को पूरा करने के लिये उच्च और अर्द्ध-कुशल दोनों रोज़गार क्षेत्रों में श्रमिकों को प्रशक्तिषति करना आवश्यक है, वशिष रूप से तब जब यह अधिक तकनीकी रूप से संचालित हो रहा है।
- स्नातक डिग्री के साथ व्यावसायिक कार्यक्रम: व्यावसायिक शक्तिषा को पारंपरिक डिग्री के साथ संयोजित करने से छात्रों को वनिरिमाण क्षेत्र में आवश्यक व्यावहारिक कौशल प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है, जिससे इस क्षेत्र में उनकी रोज़गार कषमता में सुधार होता है।

